

विचार बिन्दु

अपनी नम्रता का गर्व करने से अधिक निंदनीय और कुछ नहीं है। —मारकस

गरीबी पर चिंता बहुत, मगर बढ़ रही अमीरों की अमीरी

आजादी के बाद से ही हमारे नेता गरीबों की हमेशा चिंता की बातें ही नहीं करते रहे हैं, बल्कि गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने के दावे लेकर भी सामने आते रहे हैं। एक समय गरीबी हटाओ बड़ा नारा हुआ करता था जिस पर भरोसा करके अवाग नेताओं को सत्ता में बिठाया करती थी। कभी समाजवाद के जरिए गरीब की हालत सुधार कर उसके और अमीर के बीच की सीमा रेखा मिटाने के जतन किये गये, तो कभी खुली आर्थिक नीतियों से सबकी झोलियां भरने के उद्यम किए गये। लेकिन हर बार घूम-फिर कर यही बात सामने आई कि अमीरों की अमीरी और गरीबों की संख्या बढ़ रही है। अब तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सार्वजनिक रूप से गरीबों की 'बढ़ती' संख्या पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि "धीरे-धीरे गरीबों की संख्या बढ़ रही है और धन कुछ अमीर लोगों के हाथों में केंद्रित हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को इस तरह से बढ़ना चाहिए कि रोजगार पैदा हो और ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि "हम एक ऐसे आर्थिक विकल्प पर विचार कर रहे हैं जो रोजगार पैदा करेगा और अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देगा।"

जब कोई केंद्रीय मंत्री ऐसे आर्थिक विकल्प की बात करता है जिसमें वैसी अर्थव्यवस्था बनाना हो जो रोजगार पैदा करे तब सवाल उठता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था कैसी होगी और वे क्या बाधाएं हैं जो ऐसा नहीं होने देती? हर बार हम इसी पेच में फंस जाते हैं कि अर्थव्यवस्था ठीक होगी तो रोजगार बढ़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था छलांग लगा कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है फिर भी प्रधान मंत्री को अपने भाषणों में देश की 80 प्रतिशत आबादी को गरीब बताना पड़ता है। इससे यह समझ में आ जाना चाहिए कि अर्थव्यवस्था बढ़ने से गरीबी नहीं मिटती बल्कि अमीरों की अमीरी बढ़ती है। अब समय आ गया है कि इससे उल्टा सोचा जाए। रोजगार बढ़ेगे तब ही देश की अर्थव्यवस्था के साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। इसके लिये जरूरी है कि देश के गरीब लोगों के हाथों में रोजगार पाने का हुनर दिया जाय ताकि वे देश की अर्थ व्यवस्था में उत्पादक रूप से शामिल हो सके। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी घट कर 14 प्रतिशत रह गई है, मगर उस पर अब भी 48 प्रतिशत आबादी निर्भर करती है। यह अवहनीय स्थिति है। इस ग्रामीण आबादी को अन्य उत्पादक क्षेत्रों में शिफ्ट करना ही एक रास्ता है। यह तभी हो सकता है जब उनकी गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा तथा काम-काज के हुनर की दक्षता का प्रशिक्षण मिले। अभी हमारी शिक्षा व्यवस्था भेद करती है। अमीर अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर लेता है, मगर गरीब ऐसा नहीं कर पाता है और उसके बच्चे फिसड्डी रह जाते हैं। ऐसे में क्या किया जाय? इसके लिए जाने-माने जनसंख्याविद् डॉ. देवेन्द्र कोठारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मानव संसाधन विकास का एक उत्तम मॉडल बना कर दे चुके हैं। यह मॉडल, जो अपने लिए बजट में किसी अलग प्रावधान की मांग नहीं करता, को देश-दुनिया के अकादमिक क्षेत्रों में तो खूब सराहना मिली किन्तु हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों को उसे देखने समझने की फुरसत नहीं मिली।

वैश्विक अनुभव से भी पता चलता है कि सामाजिक कल्याण के पहलुओं पर अधिक ध्यान देने वाले देश मानव संसाधनों की गुणवत्ता को बढ़ा कर सफलतापूर्वक अपनी आय या विकास के स्तर को अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ा सकते हैं। यह भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। भले ही विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारे नेताओं द्वारा ज्ञान-अर्थव्यवस्था (नॉलेज इकोनोमी) के निर्माण की बातें बढ़-चढ़ कर की जाती रही हैं, किन्तु मानव संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करने में देर पीछे रह गया है। निश्चित रूप से यह स्पष्ट है कि मानव विकास को बेहतर बनाने के लिए अधिक संसाधनों के आवंटन के साथ काम-काज में तत्काल सुधार की आवश्यकता है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि भारत के मानव विकास के प्रयास पिछले दशकों में किए गए शुरुआती लाभ के बाद लड़खड़ा

गए हैं। हालांकि समग्र रूझान अब भी दिखाते हैं कि 1990-2022 में भारत के मानव संसाधन सूचकांक (एचडीआई) में 1.24 प्रतिशत वार्षिक औसत सुधार हुआ जो वैश्विक सुधार की गति से दोगुना अधिक होने के करीब रहा है, किन्तु बाद में यह अंतर कम हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत की एचडीआई वृद्धि दर, जो पहले 1990-2000 में 1.22 प्रतिशत से बढ़कर 2000 और 2010 के बीच 1.56 प्रतिशत हो गई थी, अब 2010-22 की अवधि में लगभग एक तिहाई घटकर केवल 0.99 प्रतिशत रह गई। वैश्विक मानव

विकास सूचकांक (एचडीआई) रैंकिंग में भारत का स्थान 2022 में एक पायदान बढ़कर 134वें स्थान पर पहुँच गया, जो उसके पिछले वर्ष से एक पायदान ऊपर था। भारत मानव विकास की मध्यम श्रेणी में है और हाल के वर्षों में दिखाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ नहीं है। वर्ष 2015 और 2022 के बीच भारत की रैंक केवल चार पायदान ऊपर बढ़ी है। अन्य देशों को देखते हुए यह एक बड़ी गिरावट है इस अवधि के दौरान अन्य देशों ने अधिक प्रभावशाली लाभ दर्ज किए हैं। परेशान करने वाली बात यह है कि भारत की एचडीआई रैंकिंग इसकी वैश्विक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) रैंकिंग से छह पायदान नीचे है, जो इसके विकास के अनुमानित स्तर को दर्शाती है। यह उन देशों की बढ़ती संख्या के बिल्कुल विपरीत है, जिन्होंने सामाजिक कल्याण के लाभों को बढ़ावा देकर अपनी आय या विकास रैंकिंग की तुलना में उच्चतर मानव विकास रैंकिंग में बढोतरी सुनिश्चित की है।

मानव संसाधन विकास के लिए भारत की कमजोर तैयारी और प्रदर्शन स्कूली शिक्षा में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रति वर्ष जारी होने वाली 'असर' की रिपोर्टें बार-बार बताती आई हैं कि सरकारी प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई की हालत सोचनीय है। यह भी किसी से छुपा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में केवल अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चे ही पढ़ने आते हैं। हमें नही मालूम गडकरी साहब जिस वैकल्पित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं वह क्या है लेकिन डॉ. कोठारी कहा करते थे कि सरकार को अमीरों की पढ़ाई का काम उनकी निजी व्यवस्था पर छोड़ कर अपना पूरा ध्यान केवल गरीब की शिक्षा पर लगाना चाहिए। अमीर अपना हाल संपाल लेंगे और सरकार को अपने संसाधन व ऊर्जा गरीबों के बच्चों की शिक्षा पर लगानी चाहिए। इन प्रयासों में स्कूली शिक्षा का ढांचा सुधारने तथा वहां गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना तो है ही, किन्तु साथ ही गरीब बच्चों के स्वास्थ्य की भी जिम्मेवारी लेनी होगी। बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा तो स्कूल नियमित किस प्रकार आएगा और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। यह केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ने आने वाले बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल कर देने भर से नहीं होगा। उनके परिवारों के सम्पूर्ण स्वास्थ्य के उपाय करने होंगे। उसके लिए उनके परिवारों की स्वच्छता का भी ध्यान रखना होगा। तभी गरीब बच्चे स्वस्थ रह कर स्कूलों में रुचिकर माहौल में अपनी पढ़ाई बरकरार रख सकेंगे। ऐसे गरीब परिवारों का नया डाटा बनाने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ सरकारी स्कूलों को ले लीजिए। उनमें नामांकित बच्चों का डाटा तैयार पड़ा है। बस उनके परिवारों तक पहुंचना है। उन परिवारों को जो मदद करनी है उसकी योजनाएं पहले से ही चल रही है। उन योजनाओं को सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चों के परिवारों पर केंद्रित करनी है। किसी भी अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं है। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत होगी तो वे उच्च शिक्षा में भी बेहतर कर पाएंगे और अमीर बच्चों की प्रतिस्पर्धा में आ सकेंगे। वे उच्च शिक्षा में न जाकर भी हुनर के प्रशिक्षण लेकर उत्पादक कामों में लग कर देश की अर्थ व्यवस्था में खुद को शामिल कर पाएंगे। इससे देश की अर्थव्यवस्था उत्पादकता उन्मुख होगी जिसमें सबकी समान भागीदारी होगी। इससे वैसा समता वाला समाज बन सकेगा जिसकी भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है। भारत के सबसे गरीब 40 प्रतिशत के पास जहां कुल आय का केवल 20 प्रतिशत है, वहीं सबसे अमीर एक प्रतिशत के पास 21.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। यह विकास के लिए एक बड़ी बाधा है क्योंकि अध्ययनों से पता चलता है कि आय के अत्यधिक केंद्रीकरण से गरीब सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। डॉ. कोठारी का एचडी प्लस मॉडल हो या कोई और हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति संविधान निर्देशित राज्य की जिम्मेवारी निभे बिना कुछ नहीं हो सकता। खुली अर्थ व्यवस्था में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का जबरदस्त निजीकरण हुआ है। दोनों क्षेत्रों में निजी सेवाएं मुनाफा कमाने के लिए सुरसा की तरह मुंह फाड़ती सबको दिख रही है। यह निजीकरण सार्वजनिक सेवाओं की कीमत पर हो रहा है। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर गरीब तो सार्वजनिक सेवाओं पर ही निर्भर हैं और वह वहां अपने को पिटा हुआ, उठा हुआ महसूस करता है। अर्थव्यवस्था में सबकी भागीदारी के लिए यदि राज्य आज काम शुरू करता है तो उसके परिणाम आने में कम से कम दस वर्ष लगेंगे जब गरीब बच्चे गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा पूरी कर हुनर के प्रशिक्षण के लिए तैयार होंगे। गडकरी साहब ने जिस वैकल्पिक मॉडल की बात की है उसमें इन चुनौतियों का सामना करने की व्यवस्था है, हमें नहीं मालूम।

—अतिथि संपादक,
राजेन्द्र बोड़ा
(वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक)



पंडित अनिल शर्मा

शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।
आज यमघट योग सूर्योदय से रात्रि 4:50 तक है। रवियोग रात्रि 4:50 तक रहेगा। राजयोग रात्रि 4:50 से सूर्योदय तक है। आज भद्रा रात्रि 1:37 से आरम्भ होगा। आज चौमासी चौदस (जैन), शिवशयन चतुरदशी है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:08 तक, शुभ 10:50 से 12:32 तक, चर 3:56 से 5:38 तक, लाभ 5:38 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:43, सूर्यास्त 7:20

राशिफल

बुधवार 9 जुलाई, 2025

आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, चतुरदशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, मूल नक्षत्र रात्रि 4:50 तक, बह्य योग रात्रि 10:9 तक, गर करण दिन 1:08 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-धनु, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।
आज यमघट योग सूर्योदय से रात्रि 4:50 तक है। रवियोग रात्रि 4:50 तक रहेगा। राजयोग रात्रि 4:50 से सूर्योदय तक है। आज भद्रा रात्रि 1:37 से आरम्भ होगा। आज चौमासी चौदस (जैन), शिवशयन चतुरदशी है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:08 तक, शुभ 10:50 से 12:32 तक, चर 3:56 से 5:38 तक, लाभ 5:38 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 5:43, सूर्यास्त 7:20



मेघ

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।



तुला

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। शुभ संदेश प्राप्त होंगे।



वृष

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आज बनने कार्य बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।



वृश्चिक

व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नीकरीयता व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मिथुन

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।



धनु

परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कर्क

व्यक्तिगत परेशानियों से राहत मिल सकती है। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मकर

मन में असंतोष बना रहेगा। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। अर्नाल कार्यों में समय खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।



सिंह

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कुंभ

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खेत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।



कन्या

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मीन

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

सफलता की कहानी-चित्तौड़गढ़ की भगवानी बाई को सामाजिक सुरक्षा का संबल मिला

पं.दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित शिविरों का उद्देश्य यही है - अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक संवेदनशीलता के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। इसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ जिले की इंगला पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नाडाखड़ा निवासी 63 वर्षीय भगवानी बाई की कहानी एक मिसाल बन गई है। भगवानी बाई के परिवार में कोई नहीं है, आय का कोई स्थाई स्रोत नहीं, पात्रता होते हुए भी जागरूकता की कमी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव में वर्षों से वृद्धावस्था पेंशन से वंचित थी। उसे

छोटे-छोटे और जरूरी खर्च के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसलिए आत्मसम्मान को खटकता भी था। नाडाखड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में भगवानी बाई ने अपनी व्यथा उपखंड अधिकारी को बताई। उपखंड अधिकारी के निर्देश पर मौके पर ही दस्तावेजों का सत्यापन कर भगवानी बाई की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई। अब भगवानी बाई को हर माह पेंशन की राशि नियमित रूप से प्राप्त होगी जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर एक नई शुरुआत कर सकेंगी। उनके चेहरे पर संतोष और आंखों में उम्मीद



की चमक यह सिद्ध करती है कि यह योजना कितनी प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा जी को मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने

इस कैम्प में आधे घंटे में मेरा काम करवा दिया। वे इसी तरह जनता की सेवा करते रहें, हम सब का आशीर्वाद और स्नेह उनकी ताकत बने।

■ उपखंड अधिकारी के निर्देश पर मौके पर ही दस्तावेजों का सत्यापन कर भगवानी बाई की वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई

आर्टिकल के संकलन, लेखन और सम्पादनकर्ता चित्तौड़गढ़ सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय में कार्यरत तुलसीराम कंडारा, सुनील पाराशर और आरिफ।

सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों पर राजनीतिकरण



अशोक कुमार

सार्वजनिक क्षेत्र में, बिना राजनीतिकरण के विभिन्न मुद्दों पर विचार ही नहीं किया जाता या हो पाता है। यह एक गहरी जड़ें जमा चुकी प्रवृत्ति है जिसके कई कारण और परिणाम हैं।

सत्ता और प्रभाव की होड़: राजनीति का मूल ही सत्ता प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है। किसी भी मुद्दे पर चर्चा या निर्णय का इस्तेमाल अक्सर राजनीतिक दलों अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाने, विरोधियों को कमजोर

करने या अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं।

वोट बैंक की राजनीति: विभिन्न समुदायों, जातियों या वर्गों को लक्षित करने के लिए मुद्दे अक्सर राजनीतिक रंग ले लेते हैं। दल विशेष मुद्दों को इस तरह से उठाते हैं जिससे उन्हें किसी विशिष्ट वोट बैंक का समर्थन मिल सके, भले ही समस्या का वास्तविक समाधान कुछ और हो।

मीडिया का प्रभाव: आज के दौर में मीडिया (खासकर न्यूज चैनल) भी अक्सर मुद्दों को सनसनीखेज बनाने और राजनीतिक बहस में बदलने में भूमिका निभाता है। टीआरपी (TRP) और व्यूअरशिप के लिए मुद्दों को राजनीतिक चरम से दिखाना आम बात हो गई है।

विचारभारतमक ध्रुवीकरण: विभिन्न राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी विचारधाराएं होती हैं। जब कोई मुद्दा सामने आता है, तो उसे अक्सर इन विचारधाराओं के अनुरूप ढाला जाता है, जिससे समस्या के मूल समाधान

से हटकर वैचारिक टकराव शुरू हो जाता है।

जवाबदेही से बचना: कई बार राजनीतिकरण का इस्तेमाल किसी समस्या के लिए जवाबदेही से बचने के लिए भी किया जाता है। जब कोई मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बन जाता है, तो असली समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाता है।

प्रचार और दुष्प्रचार: सोशल मीडिया के दौर में, किसी भी मुद्दे को आसानी से राजनीतिक रंग दिया जा सकता है, फिर चाहे वह सही जानकारी के साथ हो या गलत। दुष्प्रचार (misinformation) और फेक न्यूज (fake news) का इस्तेमाल भी राजनीतिकरण को बढ़ावा देता है।

इसके परिणाम समाधान में देरी: जब मुद्दों पर राजनीतिक बहस हावी हो जाती है, तो उनके वास्तविक समाधान पर ध्यान कम हो जाता है या उसमें अनावश्यक देरी होती है।

गंभीरता का अभाव: गंभीर और जटिल मुद्दे अक्सर सतही राजनीतिक बयानबाजी में सिमट कर रह जाते हैं, जिससे उनकी गहराई और गंभीरता कम हो जाती है।

जनता में भ्रम: लगातार राजनीतिकरण से जनता में भ्रम पैदा होता है कि असली समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे होगा। वे अक्सर राजनीतिक दलों के दावों और प्रतिदावों के बीच फंस जाते हैं।

राष्ट्रहित की उपेक्षा: कई बार राजनीतिकरण लाभ के लिए राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर भी समझौता कर लिया जाता है।

संस्थाओं पर दबाव: राजनीतिक दबाव के कारण कई स्वतंत्र संस्थाएं भी निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाती, क्योंकि उनके निर्णयों को भी राजनीतिक चरम से देखा जाता है।

क्या बिना राजनीतिकरण संभव है? पूर्ण रूप से बिना राजनीतिकरण के मुद्दों पर विचार करना एक आदर्श स्थिति हो सकती है, लेकिन व्यवहार में यह काफी

मुश्किल है। राजनीति लोगों की आकांक्षओं और जरूरतों का प्रतिनिधित्व करने का माध्यम है, और स्वाभाविक रूप से कोई भी मुद्दा जो समाज को प्रभावित करता है, वह राजनीतिक दलों के लिए प्रासंगिक हो जाता है।

हालांकि, महत्वपूर्ण यह है कि राजनीतिकरण इस हद तक न बढ़ जाए कि वह समाधान और विकास के रास्ते में बाधा बने। एक स्वस्थ लोकतंत्र में, राजनीतिक बहस होनी चाहिए, लेकिन यह बहस तथ्यों और समाधान पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल आरोप-प्रत्यारोप या वोट बैंक की राजनीति पर। सार्वजनिक विचार-विपरीत में अधिक परिपक्वता, मीडिया की अधिक जिम्मेदारी और राजनीतिक दलों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की भावना ही इस प्रवृत्ति को कम करने में मदद कर सकती है।

—अशोक कुमार,

पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय, विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

चातुर्मास आत्मशुद्धि, संयम और सामाजिक सद्भाव का विशेष काल है : राज्यपाल बागड़े

राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े ने भीलवाड़ा में चातुर्मासिक मंगल प्रवेश के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की

कभीलवाड़ा, (निसं)। राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े ने कहा कि चातुर्मास आत्मशुद्धि, संयम और सामाजिक सद्भाव का विशेष काल है, जिसमें साधु-संत एक स्थान पर उभरकर साधना, ध्यान और तपस्या करते हैं तथा समाज को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े ने मंगलवार को नैतिक चातुर्मास महोत्सव समिति भीलवाड़ा के तत्वावधान में सुभाष नगर स्थित जैन स्थानक में चातुर्मासिक मंगल प्रवेश के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम संबोधित किया।

राज्यपाल ने कहा कि जैन धर्म जीवदया, अहिंसा और आत्मशुद्धि का प्रतीक है तथा चातुर्मास के माध्यम से इन मूल्यों को जनमानस तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने कहा कि सच्चा साधु वही है जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है और दूसरों के हित में किया गया कार्य ही सच्ची सिद्धि है। यह परंपरा भगवान महावीर के काल से चली आ रही है, जिसका उद्देश्य समाज में नैतिक जागरूकता और



राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े ने भीलवाड़ा में सुभाष नगर स्थित जैन स्थानक में चातुर्मासिक मंगल प्रवेश के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।

आध्यात्मिक चेतना जागृत करना है। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि चातुर्मास के दौरान दिए जाने वाले प्रवचन व्यक्ति के अंतर्मन को जागृत करते हैं और समाज में सकारात्मक सोच का संचार करते हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को मिटाने के अनेक प्रयास इतिहास में हुए, लेकिन इसकी गहराई और मूल्यों

के कारण यह संस्कृति आज भी अधुण बनी हुई है। अपने संबोधन में राज्यपाल ने नवीन शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि यह नीति बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के साथ-साथ उनके नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन पर बल देती है। उन्होंने कहा कि नवीन शिक्षा नीति के माध्यम से ऐसे शिक्षाविद् तैयार होंगे, जो आधुनिक ज्ञान

के साथ भारतीय सांस्कृतिक विरासत को भी आत्मसात करेंगे। राज्यपाल बागड़े ने मंच पर विराजित जैन साध्वियों से आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके द्वारा समाज को दिए जा रहे आध्यात्मिक मार्गदर्शन की सराहना की। राज्यपाल के दौरे के दौरान कार्यक्रम स्थल एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा समुचित तैयारियों की गई

■ राज्यपाल हरीभाऊ बागड़े ने मंच पर विराजित जैन साध्वियों से आशीर्वाद प्राप्त किया

थी। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संघू के निदेशानुसार सुरक्षा, यातायात, भीड़ प्रबंधन एवं अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त प्रबंध सुनिश्चित किए गए थे, जिससे कार्यक्रम सुचारुवर्धित रूप से संचल हुआ। इस अवसर पर मध्यप्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद दामोदर अग्रवाल, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, मंडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, आसंद विधायक जम्बर सिंह सांखला, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आब्या , महापौर राकेश पाठक, जनप्रतिनिधि प्रशांत मेवाड़ा, पूर्व विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

आजादी के बाद देवपुरा मार्ग को कानूनी मान्यता मिली

अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ने ग्राम देवपुरा के लोगों को राहत दी

नसीराबाद, (निसं)। नसीराबाद उपखंड की ग्राम पंचायत राजगढ़ में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ने ग्राम देवपुरा के लोगों के लिए ऐतिहासिक राहत का काम किया। शिविर में वर्षों से लंबित मांग को पूरा

करते हुए गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला रास्ता पहली बार राज्यस् रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।

जानकारी के अनुसार देवपुरा, जो गुर्जर बाहुल्य इलाका है, में आजादी के बाद से आबादी तक जाने वाला मुख्य मार्ग राज्यस् रिकॉर्ड में दर्ज नहीं

था। इससे किसानों को कृषि भूमि के उपयोग और तकनीकी कार्यों में लगातार दिक्कत आ रही थी। शिविर में ग्रामीणों ने इस गंभीर समस्या को उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव और तहसीलदार समता यादव के सामने रखा।

शिविर के दौरान अधिकारियों ने मौके पर राज्यस् टीम के साथ स्थिति का जायजा लिया और तुरंत ही रास्ते को राज्यस् रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। इस आदेश के साथ ही ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान हो गया और

उन्हें बड़ी राहत मिली। ग्रामीणों और ग्राम पंचायत राजगढ़ ने उपखंड प्रशासन और राज्यस् विभाग की टीम का आभार जताया। उनका कहना है कि इस फैसले से भविष्य में विकास कार्यों और सुविधाओं के विस्तार में भी मदद मिलेगी।



सीए परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कृष्ण कुमार शर्मा का विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सम्मान किया।

व्यक्तित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए।

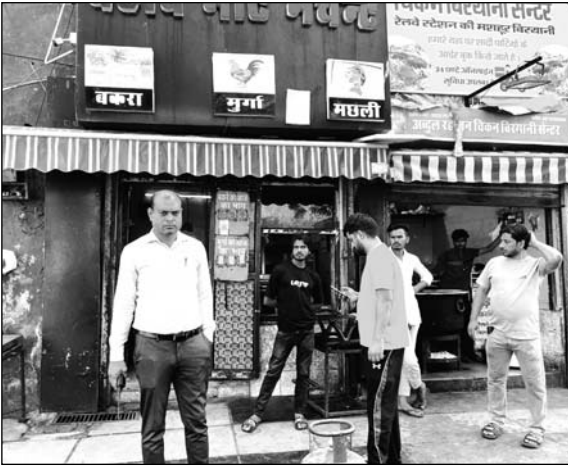
लेखाधिकारी, सेवानिवृत्ति सहायक कृष्ण कुमार शर्मा, ईश्वरीप्रसाद शर्मा, अन्नपूर्णा रसोई के संचालक विष्णु शर्मा, सेवानिवृत्ति सहायक अभिराम शर्मा, देवकीनन्दन शर्मा, श्री ब्राह्मण सन्त समिति तिलक नगर के वरिष्ठ सचिव पंडित बनवारीलाल शर्मा, एलआईसी लालचंद शर्मा, राजस्थान रोडवेज संस्थान संभागध्यक्ष दिनेश शर्मा जर्घा सेवानिवृत्त अमीन रामेश्वर प्रसाद सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों रहे। कृष्ण कुमार शर्मा के पिता पूरन शर्मा ने सभी उपस्थित अतिथियों को आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्रतिबंधित दिन मंगलवार को खुली मीट की दुकानें, निगम ने की सीज

300 किलो मछलियां की जब्

जयपुर। हेरिटेज नगर निगम की सिविल लाइंस जोन टीम और पशु प्रबंधन शाखा द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर प्रतिबंधित दिवस पर खुले मीट की दुकानों को बंद करवाया गया। वहीं, 22 गोदाम क्षेत्र में एक ट्रक में लाई गई 300 किलो अवैध मछली नष्ट की गई है।

यह पूरा अभियान हेरिटेज नगर निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल के निर्देश पर चलाया गया, जिसकी अगुवाई सिविल लाइंस जोन के उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने की। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल के निर्देश पर मंगलवार सुबह सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त जब रेलवे स्टेशन हसनपुरा क्षेत्र पहुंचे तो उन्होंने पाया कि प्रतिबंध के बावजूद मीट की दुकानें संचालित हो रही थीं, जो निगम के नियमों का खुला उल्लंघन था। ऐसे में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने तुरंत पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा को मौके पर बुलाया और कार्रवाई के निर्देश दिए। पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके



नगर निगम की सिविल लाइंस जोन टीम और पशु प्रबंधन शाखा ने संयुक्त अभियान चलाकर प्रतिबंधित दिवस पर खुले मीट की दुकानों को बंद करवाया ।

पर पहुंचकर बिना लाइसेंस संचालित दो दुकानों को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया। यह दुकानें पूर्व में भी नियम उल्लंघन के चलते चिन्हित की जा चुकी थीं।

इसके बाद उपायुक्त सुनील बैरवा ने डीएलबी कार्यालय के समीप 22 गोदाम पुलिया के नीचे

हेरिटेज निगम आयुक्त के निर्देश पर सिविल लाइन जोन की कार्रवाई

निधि पटेल ने बताया कि अवैध मांस और मछली विक्रय शहर की स्वच्छता व्यवस्था और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। मंगलवार को सरकार द्वारा मीट मछली की दुकानों पर पाबंदी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम भविष्य में भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण और सख्त कार्रवाइयों को जारी रखेगा। इस दौरान निगम आयुक्त ने आमजन से अपील की कि वे ऐसे अवैध व्यापार को सूचना तुरंत निगम प्रशासन को दें, ताकि त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकें। वहीं, आमजन ने निगम की इस तत्परता और सख्ती की सराहना की है। लोगों का मानना है कि इस प्रकार की कठोर कार्रवाई से शहर में अव्यवस्था पर लगाम लगेगी और स्वच्छ, सुसंछित वातावरण की दिशा में ठोस कदम बड़ेगा।

हेरिटेज निगम ने हटाए अतिक्रमण

जयपुर। सड़क और बरामदे पर अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ हेरिटेज निगम लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। मंगलवार को हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल के निर्देश पर उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने अभियान चलाया। इस दौरान निगम दस्ते ने छोटी चौपड़, चांदपोल, वनस्थली मार्ग, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैप, 22 गोदाम पुलिया, घाटगेट, ट्रांसपोर्ट नगर, ब्रह्मपुरी इलाके में अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया।

मानसागर में मछलियों को दाना डालने पर लगेगी पाबंदी

‘जल महल की पाल पर अतिक्रमण होने पर की जाएं सख्त कार्रवाई

जयपुर। जल महल पर सफाई सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हेरिटेज निगम सख्त कदम उठाने जा रहा है। इस

संबंध में हेरिटेज निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने मानसागर मछलियों को दाना डालने पर पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं।

इसके अलावा आयुक्त निगम ने कहा कि जल महल की पाल पर अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाए और सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंदगी फैलाने

पर भारी जुर्माना राशि वसूल की जाए। अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सामान जब्द किया जाए और उसे छोड़ा नहीं जाए। नहीं मानने पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाए। निगम आयुक्त डॉ निधि पटेल ने निर्देश दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते

स्कूल फीस रिवीजन कमेटी को लेकर याचिका निस्तारित

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल फीस से जुड़े विवादों की सुनवाई को लेकर रिवीजन कमेटी का गठन नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है। अदालत ने कहा कि रिवीजन कमेटी का गठन हो चुका है और कमेटी ने याचिकाकर्ता के संबंध में डिबीजनल कमेटी के आदेश को गलत मानते हुए उसे दो माह में नए फिरे से आदेश पारित करने को कहा है। जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीट ने यह आदेश भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बीएस छाबाने ने कहा कि रिवीजन कमेटी का गठन किया जा चुका है और इसका गजट नोटिफिकेशन भी हो चुका है। वहीं कमेटी ने याचिकाकर्ता के संबंध में डिबीजनल कमेटी के आदेश को गलत मानते हुए उसे दो माह में नए फिरे से आदेश पारित करने को कहा है। ऐसे में याचिका को निस्तारित

किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीट ने याचिका को निस्तारित कर दिया है।

याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल की फीस निर्धारण को लेकर स्कूल फीस कमेटी ने निर्णय लिया था। इस कमेटी के आदेश को कुछ अभिभावकों ने डिबीजनल कमेटी के समक्ष चुनौती दी। वहीं डिबीजनल कमेटी ने स्कूल फीस कमेटी के आदेश को गलत माना। याचिका में कहा गया कि फीस नियंत्रण अधिनियम की धारा दस में डिबीजन कमेटी के आदेश को चुनौती देने के लिए रिवीजन कमेटी के गठन का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार ने बीते नौ साल से इस रिवीजन कमेटी का गठन ही नहीं किया है। जबकि मई, 2024 में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में अंडरटेकिंग दी थी कि तीन सप्ताह में रिवीजन कमेटी का गठन कर लिया जाएगा।

जेडीए ने दो स्थानों से अतिक्रमणों को हटाए

जयपुर । जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-2 में विद्याधर नगर अलका सिनेमा के सामने रोड़ न.1 की फुटपाथ, सडक सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-7 में टैगोर नगर हनुमान बाटिका अजमेर रोड पर रोड सीमा में पेच रिपेयर कार्य को ध्वस्त कर रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र बिश्नोई ने बताया को जोन-02 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित विद्याधर नगर अलका सिनेमा के सामने रोड़ न. 1 की फुटपाथ, सडक सीमा पर करीब 15 स्थानों पर अस्थायी अतिक्रमण कर लगाये गये थडी, टेले, टेबल, कुर्सियां,

बांस, तम्बू, तिरपाल, पत्थर की पट्टियां इत्यादि लगाकर अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-02 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से हटवाया गया फुटपाथ, रोड सीमा को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

टैगोर नगर हनुमान बाटिका अजमेर रोड पर सडक सीमा में आ रहे अवैध अतिक्रमण 04 टोनशेडनुमा कोठरी, लेट-बॉथ, बाउन्ड्रीवाल इत्यादि अवैध निर्माण अतिक्रमणों को निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया।

जलभराव निस्तारण के लिए युद्धस्तर पर अभियान जारी

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण वर्षा के दौरान उत्पन्न हो रही समस्याओं-विशेषतः सड़कों की क्षति और जलभराव-के निस्तारण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आमजन की सुविधा एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेडीए द्वारा शहरभर में पेच रिपेयर कार्य व जलनिकासी की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि हाल की भारी वर्षा के कारण कई प्रमुख सड़कों में पंच रिपेयर कार्य को आवागमन में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए, जेडीए ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधियंताओं को अपने-अपने क्षेत्र में पेच रिपेयर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जेडीए की प्राथमिकता शहरवासियों को बेहतर सड़कें उपलब्ध कराना है।

केबिनेट मंत्री कुमावत ने सरकारी आवास पर सुनी समस्याएं

जयपुर। राजस्थान सरकार के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोरामन कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन की परियोजनाओं के निस्तारण के लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्या का समाधान हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस

ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चयनित कनिष्ठ लिपिक संगीता गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) की टीम ने कार्रवाई करते हुए ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से नकल कर चयनित कनिष्ठ लिपिक संगीता बिश्नोई को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी राजस्थान जयपुर वीके सिंह ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की ओर से कनिष्ठ न्यायिक सहायक लिपिक ग्रेड-द्वितीय एवं लिपिक ग्रेड-द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (2022) 12 मार्च 2023 एवं 19 मार्च 2023 को दिन में समय 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई थी। आरोपित संगीता बिश्नोई का परीक्षा 19 मार्च 2023 को परीक्षा केन्द्र आरएनबी यूनिवर्सिटी बीकानेर (राजस्थान) था । संगठित नकल गिरोह के मुख्य आरोपित पौरव कालेर निवासी छाप



जिला चूरू ने सालासर से मोबाइल फोन के माध्यम से आरोपित संगीता बिश्नोई को परीक्षा केन्द्र में ब्ल्यूटूथ डिवाइस से प्रश्न पत्र के उत्तरों की नकल करवाई थी। संगीता बिश्नोई उक्त सार्वजनिक प्रतियोगी परीक्षा के बीच चयनित होने गई थी एवं धोखाधड़ी पूर्वक कनिष्ठ श्रेणी लिपिक (ग्रेड-द्वितीय) के पद पर

ताल कटोरा की पाल पर खिलाए जाएंगे पारंपरिक खेल

जयपुर। हेरिटेज निगम की ओर से तीज महोत्सव आयोजन के तहत इस बार शहरवासियों को पारंपरिक खेल भी खिलाए जाएंगे। जिसके लिए हेरिटेज निगम प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में हेरिटेज निगम की सांस्कृतिक समिति चेयरमैन ज्योति चौहान ने बताया कि हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव के नेतृत्व में पारंपरिक तीज त्यौहार पर इस बार नगर निगम हेरिटेज की ओर भव्य आयोजन किए जाएंगे। जिससे शहरवासियों को हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी भी मिले। ऐसी के तहत तीन दिवसीय तीज महोत्सव आयोजन में कई विभिन्न गतिविधियां कराई जाएंगी। 27 जुलाई को शहरवासियों को रमाल झण्डा, म्यूजिकल चेयर, खो खो, सितोलिया जैसे पारंपरिक खेल खिलाए जाएंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कच्ची घोड़ी, केमल कार्ट, राजस्थानी फांक डांस और सावन के गीतों की परफॉर्मेंस दी जाएगी। इससे पहले तीज माता की सवारी का पूजन भी किया जाएगा।

‘मुठ्ठी भर उम्मीदवारों के लिए 22 लाख के हितों की नहीं ली जा सकती बलि’

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2025 परीक्षा को पुनः आयोजित कराने के संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि मुठ्ठी भर उम्मीदवारों के शिकायत के निवारण के लिए देशभर में आयोजित की गई परीक्षा में शामिल 22 लाख अभ्यर्थियों के हितों की बलि नहीं ली जा सकती। इसके साथ ही अदालत ने परीक्षा को पुनः आयोजित कराने और बोनस अंक देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीट ने यह आदेश रोशन यादव व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाओं में कहा गया कि देशभर के 552 शहरों और 14 इंटरनेशनल केन्द्रों में नीट यूजी-2025 परीक्षा आयोजित की गई थी। जिसमें सौकर जिले में 98 परीक्षा केन्द्र बनाए गए और 31,787 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस दौरान बिजली गुल होने सहित

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का जुली ने जताया विरोध

जयपुर। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाभर जुली ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में विरोध की आवाज को कुचलना अब एक ‘नियम’ बन चुका है और असंवैधानिक तरीके से कार्रवाई करना भाजपा आदता लोकतंत्र में विरोध करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन भाजपा सरकार इस लोकतांत्रिक परंपरा को भी अपराध मान रही है। सरकार द्वारा पुलिस के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेवजह हिरासत में लेना भाजपा की तानाशाही सोच को उजागर करता है।

धौलपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जिस तरह से दमनकारी कार्रवाई की जा रही है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले सीकर, बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू और अब धौलपुर में शालिपूर्ण विरोध करने वाले युवा कांग्रेस एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जा रही है।

हाईकोर्ट ने नीट यूजी-2025 परीक्षा को पुनः आयोजित कराने के संबंध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया

अन्य समस्याओं को लेकर 15 केन्द्रों की परीक्षा प्रभावित हुई और इसमें शामिल 5,390 अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान प्रतिकूल प्रभावित हुए। याचिका में कहा गया कि जिले के कई परीक्षा केन्द्रों में पांच मिनट से लेकर 28 मिनट तक बिजली गुल रही। इस विफलता के कारण याचिकाकर्ताओं का प्रदर्शन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ और उन्हें अनावश्यक तनाव झेलना पड़ा। याचिका में यह भी कहा गया कि अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार याचिकाकर्ताओं के अंक 400 से 600 के बीच आए हैं और अधिकांश याचिकाकर्ता कट ऑफ

के करीब थे। यदि परीक्षा में व्यवधान नहीं होता तो वे उच्च अंक प्राप्त कर चयनित होते। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता एमएस राघव ने बताया कि कुल अभ्यर्थियों में से सिर्फ आधा फीसदी अभ्यर्थियों ने ही शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा केवल मुठ्ठी भर उम्मीदवार हाईकोर्ट पहुंचे हैं और 99.5 फीसदी अभ्यर्थी परीक्षा संचालन से संतुष्ट नजर आए हैं।

इसके अलावा तुफान और खराब मौसम के कारण बिजली गुल होना नियंत्रण में परे था। वहीं मामले में एक कमेटी भी गठित की गई थी। जिसने पाया कि प्रभावित परीक्षा केन्द्रों और सामान्य केन्द्रों में कोई अंतर नहीं था और ना ही याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

आयुक्त सैनी ने हिंगोनिया गौशाला का किया निरीक्षण

नगर निगम ग्रेटर की पशु प्रबंधन शाखा मिशन मोड पर

गत 5 माह में 5 हजार 500 निराश्रित गौवंश को पकड़कर हिंगोनिया गौ-पुनर्वास केंद्र पहुंचाया

नगर निगम ग्रेटर आयुक्त डॉ. गौरव सैनी के दिशा निर्देशानुसार पशु प्रबंधन शाखा द्वारा गत 5 माह में नगर निगम ग्रेटर क्षेत्राधिकार से निराश्रित 5 हजार 500 गौवंश को पकड़कर हिंगोनिया गौ-पुनर्वास केंद्र भेजा गया। इसके अतिरिक्त रोगी पशु वाहन (एंबुलेंस) द्वारा लगभग एक हजार गौवंश को उपचार हेतु गौ-पुनर्वास केंद्र हिंगोनिया के पशु चिकित्सालय में उपचार कराया गया।

60 वर्ष पुराना भूमि विवाद हल

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा आयोजित पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्मेलन पखवाड़ा- 2025 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पैंवालिया के ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ रूपवास में मंगलवार दिनांक 08.07.2025 को आयोजित शिविर में 73 बीघा कृषि भूमि को लेकर ग्रामवासी गोपाल, दयाल व हरजीराम वगैरह में लगभग 55-60 वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसे लेकर उक्त सभी कृषक अभियान में उपखण्ड अधिकारी सांगानेर हिममतसिंह के समक्ष प्रस्तुत हुए। मौके पर उपखण्ड अधिकारी तथा सरपंच पैंवालिया रामराज चौधरी, भू.अ.निरीक्षक विशाल सिंहल तथा पटवारी हल्का राहुल गंगावत के प्रयास स्वरूप उक्त भूमि के विभाजन के लिए सहमति बनी। सभी खातेदार सहमत हुए, जिसमे मौके पर ही सहमति विभाजन स्वीकृत कर राजस्व रिवाई में अमलदरपाम किया गया। इस अवसर पर समस्त खातेदारों द्वारा वही पुराने विवाद के निस्तारण पर प्रशंसन व पंचायत को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा आयोजित पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्मेलन पखवाड़ा- 2025 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पैंवालिया के ग्राम जयसिंहपुरा उर्फ रूपवास में मंगलवार दिनांक 08.07.2025 को आयोजित शिविर में 73 बीघा कृषि भूमि को लेकर ग्रामवासी गोपाल, दयाल व हरजीराम वगैरह में लगभग 55-60 वर्षों से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसे लेकर उक्त सभी कृषक अभियान में उपखण्ड अधिकारी सांगानेर हिममतसिंह के समक्ष प्रस्तुत हुए। मौके पर उपखण्ड अधिकारी तथा सरपंच पैंवालिया रामराज चौधरी, भू.अ.निरीक्षक विशाल सिंहल तथा पटवारी हल्का राहुल गंगावत के प्रयास स्वरूप उक्त भूमि के विभाजन के लिए सहमति बनी। सभी खातेदार सहमत हुए, जिसमे मौके पर ही सहमति विभाजन स्वीकृत कर राजस्व रिवाई में अमलदरपाम किया गया। इस अवसर पर समस्त खातेदारों द्वारा वही पुराने विवाद के निस्तारण पर प्रशंसन व पंचायत को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

विधायकों ने भी इलाके समस्याओं से कराया अवगत

दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए कार्य किया जा रहा है। मंत्री कुमावत ने मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान कहा कि सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए जनसुनवाई की व्यवस्था की गई है।

जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में प्रदेशभर से लोग पहुंचे। जनसुनवाई में शिक्षा, चिकित्सा, जल आपूर्ति, पेंशन, सड़क निर्माण, प्रशासनिक सेवाओं सहित अनेक विषयों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं।

केबिनेट मंत्री ने हर आवेदक की बात ने मंगलवार को सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई के दौरान कहा कि सरकार की ओर से आमजन को राहत देने के लिए जनसुनवाई की व्यवस्था की गई है।

जयपुर। राजस्थान सरकार के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोरामन कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन की परियोजनाओं के निस्तारण के लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्या का समाधान हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस

जयपुर। राजस्थान सरकार के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के केबिनेट मंत्री जोरामन कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आमजन की परियोजनाओं के निस्तारण के लिए पूरी तरह से संवेदनशील हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्या का समाधान हो, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इस

रेलवे लाइन का कार्य शुरू करने का किसानों ने किया विरोध

किसानों के विरोध जताने पर प्रशासन को बिना जमीन का कब्जा लिए ही वापिस लौटना पड़ा

खिरोड़, (निसं)। दुर्जनपुरा से गोठड़ा श्री सीमेंट कंपनी तक डाली जाने वाली रेलवे लाइन का कार्य शुरू करने के लिए संबंधित किसानों की जमीन को चिह्नित कर जमीन का कब्जा लेने प्रशासन मंगलवार सुबह नौ बजे बसावा गांव के खेतों में पहुंचा, मगर किसानों के विरोध जताने पर प्रशासन को बिना जमीन का कब्जा लिए ही वापिस लौटना पड़ा।

प्रशासन पुलिस जाबो के साथ बसावा गांव के खेतों में किसानों की अनुमति के बिना ही जबरन घुस गए और रेलवे लाइन डाले जाने का कार्य शुरू कर दिया, मगर आस-पड़ौस के किसानों ने एकत्रित होकर इस कार्य का विरोध किया। पुलिस प्रशासन का भी भारी विरोध किया गया। इस मामले में किसानों ने बताया कि हमारे खेतों में से रेलवे लाइन नहीं जाने देंगे। चाहे हमारी जान भी क्यों न चली जाए सभी किसानों ने मिलकर एक स्वर में कहा कि जान दे देंगे, मगर हमारी जमीन में से रेलवे लाइन नहीं जाने देंगे। रेलवे लाइन निरस्त किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष रतनसिंह शेखावत के नेतृत्व में किसानों ने रेलवे लाइन का जमकर विरोध किया। किसानों ने प्रशासन की



दुर्जनपुरा से गोठड़ा श्री सीमेंट कंपनी तक डाली जाने वाली रेलवे लाइन का किसानों ने विरोध किया।

इस कार्यवाही को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि किसानों की सहमति के बिना किसानों के खेतों में घुसना गलत है। प्रशासन एवं भरपूर पुलिस जाबो के साथ खेतों में रेलवे लाइन डाले जाने का काम शुरू करने के लिए संबंधित उद्देकार अपने साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में सामान लेकर आए और खेतों में काम करना शुरू कर दिया। मगर सैकड़ों की संख्या में कृषक

महिलाओं एवं पुरुषों ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके चलते प्रशासन को वापस लौटना पड़ा। किसान नेता विजेंद्र सिंह काजला ने कहा कि किसानों को डरा-धमका कर जबरन रेल लाइन डालने के लिए भूमि का अधिग्रहण करना सरकार और प्रशासन की गहमरानी हरकत है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को इन पूंजीपतियों के लिए रेल लाइन डालनी

है तो किसानों को मार्केट रेट से चार से पांच गुना भूमिका मूल्य और किसानों को पुनर्वास की सुविधा दिए जाने व प्रभावित किसानों को सरकारी नौकरी देने एवं रेल लाइन के दोनों तरफ सड़क डालनी होगी। किसान नेता नरेंद्र कड़वाल ने कहा कि अगर किसानों की सहमति के बिना प्रशासन किसानों के खेतों में घुसा तो किसानों द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर

- संबंधित किसानों की जमीन को चिह्नित कर जमीन का कब्जा लेने प्रशासन बसावा गांव के खेतों में पहुंचा
- सभी किसानों ने मिलकर एक स्वर में कहा कि जान दे देंगे, मगर हमारी जमीन में से रेलवे लाइन नहीं जाने देंगे

विरोध किया जाएगा।

रेलवे लाइन का विरोध प्रदर्शन करने वालों में राजेश दूत, शीशराम दूत, करणीराम, जगदीश प्रसाद, शिशुपाल, पंकज कुमार, मुकेश कुमार, राकेश कुमार, विक्की, महेश, भूपेश गुर्जर, मनोज मूंड, मामराज मूंड, माया देवी, सुनीता देवी, संतोष देवी, प्रभाती देवी, कमला देवी, परमेश्वरी देवी, सावित्री देवी, कमला देवी सहित सैकड़ों लोग शामिल थे।

रीट प्रमाण पत्र का वितरण समय से पहले ही बंद करने पर हंगामा

उदयपुर, (कासं)। शहर के सूरजपोल स्थित राजकीय फतह सी.सै. स्कूल में मंगलवार को रीट पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र का वितरण समय से पहले ही बंद किए जाने पर हंगामा हो गया। अभ्यर्थी विरोध पर उतर आए और प्रिंसिपल चेतन पानेरी के रूप के बाहर प्रदर्शन करने लगे।

अभ्यर्थियों का कहना था कि स्कूल प्रबंधन को स्कूल के निर्धारित समय में रीट प्रमाण पत्र वितरित करने थे, लेकिन स्टाफ एक घंटा पहले ही स्कूल से गायब हो गया। अभ्यर्थी घंटों तक इशर से उभर भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई जबाव देने वाला नहीं था। इस दौरान इस दौरान प्रिंसिपल चेतन पानेरी भी गायब थे। अभ्यर्थी उन्हें फोन करते रहे लेकिन उन्होंने

- अभ्यर्थी विरोध पर उतर आए और प्रिंसिपल के रूप के बाहर प्रदर्शन किया

कॉल नहीं उठाया। ऐसे में जब अभ्यर्थियों ने डीईओ को इसकी शिकायत की तो प्रिंसिपल तुरंत स्कूल पहुंचे। प्रिंसिपल चेतन पानेरी स्टाफ कम होने और इस वक्त प्रवेश व टीसी आदि की भार होने का कारण गिनाते रहे, जबकि स्कूल में पीटीआई सहित 65 जनों का स्टाफ है। जानकारी के अनुसार सरकारी फतह स्कूल में रीट प्रमाण का वितरण सोमवार को शुरू हुआ था। पहले दिन भी समस्या आई लेकिन दूसरे दिन

मंगलवार को हालात और खराब हो गए। यहां 60 से 70 किमी दूर कोटडा, सेमारी, खेरवाड़ा आदि ब्लॉक से महिला और पुरुष अभ्यर्थी आए थे, जिन्हें प्रमाण पत्र लेकर बस से वापस अपने घर जाना था लेकिन स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण अभ्यर्थियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। स्कूल को आठ हजार अभ्यर्थियों को रीट प्रमाण पत्र वितरित करने हैं। इसके लिए स्कूल प्रिंसिपल ने आठ काउंटर बनाए। प्रत्येक पर एक-एक हजार प्रमाण पत्र वितरित होने हैं। एक काउंटर पर दो-दो स्टाफ यानी कुल 16 स्टाफ को नियुक्त किया लेकिन वहां सिर्फ दो ही काउंटर लगे थे। बाकी काउंटर तो थे, लेकिन वहां कोई स्टाफ मौजूद नहीं था।

जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया

नसीराबाद, (निसं)। मांगलियावास थाने में दर्ज एक हत्या के मामले में आरोपियों को नसीराबाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपर लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी ने बताया कि रामपुरा धोला दाता मसूदा निवासी लक्ष्मी ने 19 मई 2025 को मांगलियावास थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, उसका पति फतेह सिंह ट्रेलर लेकर कोटपूतली से ब्यावर की ओर आ रहा था, तभी तबीजी के पास पिकअप और मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने ट्रेलर रुकवाया और शिवराज, रोहित, सत्यनारायण समेत अन्य ने फतेह सिंह के साथ गंभीर मारपीट की।

देश की पहली मोबाइल सर्जिकल रोबोटिक बस अजमेर पहुंची

अजमेर, (कासं)। देश की पहली मोबाइल सर्जिकल रोबोटिक बस मंगलवार को अजमेर पहुंची। यहां मेडिकल कॉलेज में मोबाइल रोबोटिक बस के तकनीकी कार्मिकों द्वारा जेएलएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स,

- जेएलएन मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जिकल का लाइव डेमो और प्रशिक्षण दिया
- अजमेर से पहले मोबाइल सर्जिकल रोबोटिक बस जयपुर और जोधपुर में भी ट्रेनिंग दे चुकी हैं

मेडिकल स्टूडेंट सहित अन्य स्टाफ को लाइव डेमो और ट्रेनिंग के माध्यम से रोबोटिक सर्जिकल तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। जानकारी के अनुसार अजमेर से पहले यह बस जयपुर और जोधपुर में भी ट्रेनिंग दे चुकी

</

‘सिंधु जल समझौते से बचने वाला पानी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरु को मिलेगा’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने गुसाईंसर बड़ा में अंत्योदय के शिविर का अवलोकन किया

बीकानेर, 8 जुलाई (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से रह हुए सिंधु जल समझौते से बचने वाला पानी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरु को मिलने वाला है। ये चारों जिले बड़े सीमाव्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए हैं, वो सभी पूरे होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता आए तो पूछना कि उनके वादों का क्या हुआ।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बीकानेर के गुंसाईंसर बड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का अवलोकन करने के बाद आयोजित सभा को संबोधित किया। उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र राठौड़ भी थे।

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, लेकिन हम श्री डूंगरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम करेंगे।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि श्रीडूंगरगढ़ के लिए जमीन देने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए जरूरी बजट भी दिया जायेगा। कांग्रेस ने जिस व्यापारी से घोषणा कराई थी, वो ये काम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ घोषणा की, लेकिन हम ट्रॉमा सेंटर बनाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने व्यापारी पर दबाव बनाकर सिर्फ घोषणा करवा ली, अब वो टालमटोल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि जब तक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला नहीं होगा, तब तक राजस्थान उत्कृष्ट नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इंदिरा गांधी नहर के लिए चार हजार



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर के गुंसाईंसर बड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर का निरीक्षण किया और सभा को संबोधित किया।

करोड़ रूपए दिए हैं और बीकानेर, चूरु, श्रीगंगानगर में इससे काम होगा। किसान को पानी-बिजली और बीज देने का काम हमारी सरकार ने किया है।

विधायक ताराचंद सारस्वत ने अपने भाषण में मुख्यमंत्री के समक्ष

ट्रॉमा सेंटर बनाने की मांग रखी तथा सरकारी कॉलेज की घोषणा करने की मांग की।

ताराचंद सारस्वत के भाषण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके विधायक होशियार हैं। दो मिन्ट का बोला था,

लेकिन पूरे तीन पन्ने का भाषण बोल दिया।

उन्होंने अपनी सभी मांगें रख दी हैं। जो काम अधूरे हैं, उनके बारे में भी बोल दिया और जो करवाने हैं, उनके बारे में भी बोल दिया।

उदयपुर फाइल्स फिल्म पर प्रतिबंध की माँग पर सुनवाई आज होगी

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म और उसके ट्रेलर पर बैन लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है

कहानी हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच गंभीर दूरी और तनाव पैदा कर सकती है। याचिका की 9 जुलाई, बुधवार को सुनवाई होने की संभावना है।

याचिका में कहा गया है, “फिल्म का ट्रेलर मुस्लिम समुदाय को नकारात्मक तरीके से पेश करता है, जिससे उस समुदाय के लोगों के सम्मान से जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। फिल्म बहुत भड़काऊ है और दो समुदायों के बीच फूट डाल सकती है, जिससे देशभर में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है।

याचिका कहती है कि “ट्रेलर की सामग्री खास तौर पर मुस्लिम समुदाय

■ **यह फिल्म उदयपुर में दिन दहाड़े हुई कन्हैयालाल दर्जी की नृशंस हत्या पर आधारित है। ज्ञातव्य है कि मुस्लिम कट्टरपंथी युवकों ने तलवारों से काट कर कन्हैयालाल की हत्या कर दी थी।**

■ **जमीयत के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि फिल्म से हिंदू-मुस्लिम वैमनस्यता को बढ़ावा मिलेगा और इससे देश भर में शांति और व्यवस्था बिगड़ सकती है।**

■ **फिल्म 11 जुलाई को रिलीज हो रही है।**

को निशाना बनाती दिखती है, जिसमें उनके बारे में गलत और तोड़ी-मरोड़ी गई बातें दिखाकर भाईचारे को तोड़ने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की

बिहार में 47 प्रतिशत मतदाताओं ने गणना फॉर्म जमा करवाए

नयी दिल्ली, 08 जुलाई। बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया में दो सप्ताह के अंदर चुनाव अधिकारियों को लगभग आधे मतदाताओं (47 प्रतिशत) के भरे हुए गणना-फार्म प्राप्त हो चुके हैं। यह जानकारी मंगलवार को आयोग द्वारा जारी एक विज्ञप्त में दी गयी। गणना-फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई है। आयोग ने कहा है कि बिहार में पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत 3,70,77,077 गणना फार्म मिल चुके हैं, जो राज्य में कुल 7,89,69,844 मतदाताओं की संख्या का 46.95 प्रतिशत है। आयोग ने पुनरीक्षण के लिए दिशानिर्देश गत 24 जून को जारी किए थे। आयोग ने पुनरीक्षण के काम के लिए इन दो सप्ताह में 7.90 करोड़ फॉर्म मुद्रित कराए हैं और सूची में दर्ज 97 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं (7,70,44,990) के गणना-फार्म वितरित किए जा चुके हैं। आयोग का कहना है कि अब तक 18.16 प्रतिशत फॉर्म उसके ऐप ईसीआईनेट पर अपलोड किए जा चुके हैं।

अश्वनी पंजाब ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वहीं, अब भाजपा के संगठनात्मक ढाँचे को देखते हुए अश्वनी शर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना रणनीतिक फैसला माना जा रहा है।

कांग्रेस ने माना कर्नाटक में पार्टी में अन्तर्कलह है

- **कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला ने कहा, कई विधायकों को पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से शिकायत है।**
- **लेकिन सुरजेवाला ने नेतृत्व परिवर्तन से इन्कार किया व कहा कि इस पर फैसला हाईकमान ही ले सकता है।**

मैंने उनसे कहा है कि वे ये सब मुझे लिखित में दें। हम उनका बारी बारी से हल निकालेंगे।

कांग्रेस नेतृत्व का दावा है कि राज्य में पार्टी में हालात का दबाव में हैं लेकिन आम चर्चा यह है कि शिकायतों के सामने आने से पार्टी की अंदरूनी कलह दिखने लगी है। अब सुरजेवाला ने जो रुख अपनाया है, वह बंद कمر में बातचीत

और मीडिया को निगाहों से दूर रहने का प्रयास है। उन्होंने समस्या के हल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है, जिससे लगता है कि पार्टी शिकायतों के निपटारे के मामले में कोई गंभीर कदम उठाने वाली नहीं है।

राज्य में नेतृत्व बदलाव को लेकर उठे सवालों को दरकिनार करते हुए, उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा, एक

पत्रकार की संपादक बनने की आकांक्षा हो सकती है, लेकिन इस फैसले की डोर तो चैनल मालिक के हाथ में होती है। सुरजेवाला के बयान नेतृत्व संबंधी फैसलों पर कांग्रेस हाईकमान की मजबूत पकड़ को दिखाते हैं।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के दिल्ली दौरे के बारे में पूछे जाने पर, सुरजेवाला ने स्पष्ट किया कि ये दौरे पूरी तरह से प्रशासनिक हैं। उन्होंने कहा, “वे सरकारी काम से दिल्ली जा रहे हैं—ताकि वे केन्द्र के समक्ष कर्नाटक के मसले रख सकें। यह उनका कर्तव्य है और वे इसे पूरा कर रहे हैं।”

चिराग पासवान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हत्याएं और अन्य अपराध बढ़ते जा रहे हैं। यह मेरे लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि जिस सरकार का मैं समर्थन करता हूँ, वह सुशासन के लिए जानी जाती है।

चिराग तो अब विपक्षी नेताओं जैसी भाषा बोल रहे हैं। यह चौकाने वाला है।

हालाँकि अभी तो चुनाव में समय है, देखना यह होगा कि चिराग नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ अपनी बयानबाजी को कितना आगे ले जाते हैं। यह भी देखने की बात है कि क्या वे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये लोकसभा सांसद और केन्द्रीय मंत्री पद से वाकई इस्तीफा दे देंगे या फिर वे सीट बंटवारे में अच्छी डील हासिल कर के पीछे हट जाएँगे?

जो भी हो, एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर आने वाले हफ्तों में तकरार तेज होने की पूरी संभावना है।

इज़रायल के प्र.मंत्री... ‘पुलवामा हमले के लिए विस्फोटक एमेज़ॉन से खरीदे गए थे’

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तनाव कम कराने तथा सर्बिया और कोसोवो के बीच समझौता कराने में उनके प्रयासों को अन्देखा किया। हालांकि भारत ने अधिकारिक रूप से पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए संघर्ष में ट्रंप की भूमिका का खंडन किया है और कहा है कि आपसी बातचीत से समाधान हुआ।

ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने मिश्र, बर्मा, इथियोपिया के बीच शांति बनाए रखने में मदद की है, और अब्राहम समझौते (अब्राहम कॉर्ड्स) के जरिए इज़राइल और कुछ अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने में भी उनकी भूमिका रही है।

ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में

खुद को एक शांति निर्माता बताया था और वादा किया था कि वे अपने बातचीत के कौशल से यूक्रेन और गाज़ा के युद्धों को जल्दी खत्म करवा देंगे। लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के पांच महीने बाद भी ये दोनों संघर्ष जारी हैं।

नेतन्याहू और ट्रंप के बीच हुई बातचीत में गाज़ा में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर एक समझौते पर काम करने पर चर्चा हुई। उसी दौरान, इज़राइल के अधिकारी कतर में हमास के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता कर रहे थे, जिसमें अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। ट्रंप ने बैटक से पहले ही अनुमान जताया था कि इस सप्ताह एक समझौता हो सकता है।

आतंकी वित्तपोषण की वैश्विक निगरानी संस्था एफएटीएफ ने दावा किया

नई दिल्ली, 08 जुलाई। वैश्विक आतंकी वित्तपोषण निगरानी संस्था एफएटीएफ ने दावा किया है कि फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक अमेजन से खरीदे गये थे। एफएटीएफ ने दावा किया कि 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आतंकी को पेमेंट पेपल से हुआ था।

अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए एफएटीएफ ने कहा कि वित्तीय सहायता के बिना ऐसे हमले संभव नहीं थे। एफएटीएफ ने कहा था कि वह 200 अधिकार क्षेत्रों वाले अपने वैश्विक नेटवर्क द्वारा प्रदान किए गए मामलों

को संकलित करते हुए, आतंकवादी वित्तपोषण का व्यापक विश्लेषण करेगा। भारत में आतंकवादी हमले के लिए सामग्री की खरीद के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के उपयोग की केस स्टडी देते हुए, एफएटीएफ ने कहा कि हमले में इस्तेमाल किए गए तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का एक प्रमुख घटक – एल्यूमीनियम पाउडर – ईपीओम अमेजन से खरीदा गया था। इस सामग्री का उपयोग विस्फोट के प्रभाव को बढ़

ाने के लिए किया गया था।

बता दें कि फरवरी 2019 में, जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में भारतीय सुरक्षा बलों के निशाना बनाकर एक आत्मघाती बम

विस्फोट किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 40 सैनिक मारे गए। आतंकी हमले की जांच, साजिश जैश-ए-मोहम्मद द्वारा रची गई थी।

एफएटीएफ रिपोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आतंकवादी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म

बैलट बैंक्स में। अमेरिकन व्यवस्था का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि क्या इसके नागरिक और नेता दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर उन गहरे मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं, जो इस गणराज्य को एक सूत्र में बाँधते हैं। और वे मूल्य हैं- निष्पक्षता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति साझा प्रतिबद्धता।

अगर ऐसा नहीं हो सका, तो खतरा विदेशी नहीं होगा, वह भीतर से ही आएगा।

इलेक्ट्रिक कारों से लेकर अंतरिक्ष शोध तक के उद्योगों को झकझोर देते वाले अरबपति उद्यमी एलन मस्क अब एक नई दिशा में, अमेरिकन राजनीति में कदम रख चुके हैं। अपनी नई राजनीतिक पार्टी, “अमेरिका पार्टी” की शुरुआत के साथ, मस्क ने लोकतांत्रिक इतिहास की मजबूत प्रहरी, अमेरिकी द्वि-दलीय व्यवस्था की जड़ों को चुनौती देने की कोशिश शुरू कर दी है। उन्होंने यह कदम ऐसे समय पर उठाया

ट्रंप ने 14 देशों के लिए नए टैरिफ घोषित किए

ट्रंप ने इन सभी 14 देशों के राष्ट्र प्रमुखों को पत्र भेजकर सूचित कर दिया है

- **इन देशों में जापान व दक्षिण कोरिया जैसे बड़े देशों के अलावा म्यांमार, बांग्लादेश जैसे छोटे देश भी शामिल हैं। कई देश तो ऐसे हैं जो लम्बे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे हैं।**

कारण इन्हें निर्लांबित कर दिया गया था।

ट्रंप ने ‘दृथ सोशल प्लेटफॉर्म’ पर जापान और दक्षिण कोरिया को लिखे पत्र में कहा, यदि किसी कारण से आप अपने टैरिफ बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो आप उन्हें जिस भी संख्या में बढ़ाना चाहते हैं, वह हमारे द्वारा लगाए जाने वाले 25 प्रतिशत में जोड़ दिया जाएगा।

गौरतलब है कि उच्च टैरिफ एक अगस्त से प्रभावी होंगे और विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, स्टील और एल्यूमीनियम जैसे पहले से घोषित सेक्टर टैरिफ के साथ नहीं जुड़ेंगे।

ट्रंप के पत्रों में जापान और दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी गई थी कि उनके टैरिफ में किसी भी वृद्धि के साथ ही अमेरिकी शुल्कों में भी वृद्धि कर दी जाएगी। ट्रंप ने घोषणा की कि इसी तरह के पत्र

12 अन्य देशों के नेताओं को भेजे गए, जिनमें मलेशिया, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, लाओस, टय्यूनीशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सर्बिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, कंबोडिया, थाईलैंड शामिल हैं। उन्हें यह सूचना दी गई कि अगले महीने से उन पर 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक टैरिफ लगाए जाएंगे। मलेशिया, कजाकिस्तान और ट्यूनीशिया पर टैरिफ दर 25 प्रतिशत होगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका और बिर्हाना के लिए यह 30 प्रतिशत होगी। इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत और बांग्लादेश एवं सर्बिया पर 35 प्रतिशत टैरिफ दर लागू होगी। कंबोडिया और थाईलैंड पर टैरिफ दर 36 प्रतिशत होगी, जबकि लाओस एवं म्यांमार पर यह 40 प्रतिशत तक होगी।

पत्रकार की संपादक बनने की आकांक्षा हो सकती है, लेकिन इस फैसले की डोर तो चैनल मालिक के हाथ में होती है। सुरजेवाला के बयान नेतृत्व संबंधी फैसलों पर कांग्रेस हाईकमान की मजबूत पकड़ को दिखाते हैं।

रेल मंत्री अश्विनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वैष्णव समाज में परम्परा रही है कि घर के किसी व्योयुद्ध सदस्य का निधन होता है, तो बैकुंठी निकाली जाती है। अंतिम संस्कार भी पार्थिव देह को बैठाकर ही किया जाता है।

रेल मंत्री बनने के बाद 2 अक्टूबर 2021 को पहली बार अश्विनी वैष्णव जोधपुर आए थे। इस दौरान पिता-पुत्र की मुलाकात काफी कम समय के लिए हो पाई थी, तब दाऊलाल वैष्णव ने अश्विनी वैष्णव को एक चिट्ठी लिखी।

उन्होंने लिखा- कर्तव्य को इतनी निष्ठा से निष्पादित करो कि हर रेलयात्री का चेहरा यात्रा के दौरान फूल सा खिले।

स्व. दाऊलाल वैष्णव की अंतिम यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं सहित, शहर के लोग उपस्थित थे। अंतिम संस्कार के काग़ रमशान घाट पर सीएम भजनलाल शर्मा तथा भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ भी पहुंचे।

एसआई भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

शामिल थे। महाधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में कहा कि उनकी ओर से याचिकाकर्ता के आरोपों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। उनके अनुरोध पर अदालत ने पूर्व में दिये आदेश को संशोधित कर दिया।

बहस के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि याचिका में कैबिनेट सब कमेट्री के फैसले को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाना चाहिए। इसके अलावा समान तथ्यों पर याचिका पेश की गई थी और उसे वापस लेने के आधार अदालत ने उसे खारिज कर दिया था, लेकिन नई याचिका में इस तथ्य को छुपाया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश

सुअवसर प्रस्तुत कर रही है।

एलन मस्क एक ऐसे उभरते गठजोड़ की ओर बढ़ रहे हैं। जो पारंपरिक राजनीतिक पहचान से परे है। उनकी नजर तकनीकी उद्यमियों, जो दोनों पार्टियों से निराश हैं, और युवा मतदाताओं पर है। “अमेरिका पार्टी” उन मतदाताओं का ठिकाना बन सकती है, जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक सोच रखते हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से प्रगतिशील सोच और दक्षिणपंथी अतिवाद, दोनों से सतर्क हैं।

अभी केवल इतना कहा जा सकता है कि चाहे “अमेरिका पार्टी” द्वि-दलीय प्रणाली को गिरा पाए या केवल उसमें सुधार के लिए एक धक्का दे, लेकिन उनका मतक न एक नई चर्चा की शुरुआत कर दी है। एक ऐसा देश जहाँ राजनीतिक कल्पना अक्सर जड़ जमाकर बैठ जाती है, वहाँ यह खुद में एक ऐसा झटका है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।